हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस०जे० ई०-बी(1) / 20

तारीख शिमला-2,

26 जून, 2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष रनातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग- II, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग-प्प (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2015 हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि। तारीख शिमला–2

26 जून, 2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है:-

- अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (वित्त / विधि / कार्मिक) हिमाचल प्रदेश सरकार,
- निदेशक, अनुसूचित जाति,अन्य पिछड़ा वर्ग व अन्य अल्प संख्यक मामले हिमाचल प्रदेश 2. शिमला-09
- नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-5 3

अवर सचिव (सा० न्याय एवं अधि०) हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग—II,(अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.पद का नामः विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०)

सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित)

2.पद(पदों) की संख्याः 01 (एक)

3.वर्गीकरणः वर्ग -II, (अराजपत्रित)

4.वेतनमानः i) नियमित पदधारीं के लिए वेतनमानः

पे बैण्ड ₹10300-34800 जमा ₹4200 / -ग्रेड पे।

ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्ध्यियां

₹14500 / — प्रतिमास स्तम्भ संख्या 15—क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

5.चयन पद अथवा अचयन पदः लागू नहीं।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या सविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश(आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों /स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर, निगमों /स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7.सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:

- (क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः
- i) हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/ कम्पयूटर एप्लीकेशन/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान / गणित / सांख्यिकी में स्नातकोततर की उपाधि या इसके समतुल्य।

हिमाचल प्रदेश सरकार / केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर एप्लीकेशन में कम से कम दो वर्ष की अवधि का स्नातकोततर डिप्लोमा।

या

हिमाचल प्रदेश सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी/कम्पयूटर विज्ञान/कम्पयूटर एप्लीकेशन (एम.सी.ए.) में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य।

या

डोएक (डी.ओ.ई.ए.ए.सी) सोसाइटी से "बी" स्तर का कोर्स। 8.सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं:

9.परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

10.भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः

11.प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / <u>सैकेण्डमैंट / स्थानान्तरण</u> किया जाएगाः

12.यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः

13.भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

14.सीधे भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः

15.सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः आयुः लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार भर्ती द्वारा।

लागू नहीं।

लागू नहीं।

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक

15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन। परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम आदि, यथास्थिति, आयोग/ अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:—

¼Ӏ॑॑॑संकल्पना

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अविध में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अविध नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

(ख)पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः

प्रधान सचिव / सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियांः

संविदा के आधार पर नियुक्त विशेष रनातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) को ₹ 14500 / – की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष / वर्षों के लिए

संविदात्मक उपलिख्यों में ₹ 435 / — (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम् आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V)संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।

(VI) करार अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तेः

- (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 14500 /— की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष / वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹435 /— की दर से (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे विरष्ट / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा
 पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि
 संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का
 कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है
 तो, नियुक्ति समाप्त की किए जाने के लिए
 दायी होगी।
- (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी० आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा:

परन्तु अनुपभुक्त आकरिमक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश

- एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपिश्यित से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनाधिकृत अनुपिश्यित के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपिश्यित की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
- (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेनतमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे कि एफ0आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

लागू नहीं।

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

16.आरक्षणः

17 विभागीय परीक्षा

18. शिथिल करने की शक्तिः

विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक (पी०जी०टी०) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग—II,(अराजपत्रित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यंक मामले हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह व	करार श्री	ो / श्रीमति				पत्र	/पत्री	श्री			
पश्चात् "प्रथ							_		-		
निदेशक, अनु	सूचित उ	जाति, अन्य	य पिछड़ा व	र्ग एवं अ	गल्पसंख्यंव	न मामले	हिमाच	ल प्रदेश	(जिसे	इसमें	इसके
पश्चात् "द्विती	य पक्षक	ार" कहा	गया है) के	माध्यम	से आज त	तारीख			को कि	या गय	ПΙ

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विषेश स्नातकोत्तर अध्यापक (पी0जी0टी0) सूचना प्रौद्योगिकी (श्रवण बाधित) वर्ग—प्प्(अराजपत्रित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमित दी है:—

1. यह कि प्रथम पक्षकार विशेष स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में............. से प्रारम्भ होने और... .. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अविध के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्.................................. दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत / विस्तारित की जाएगी।

- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ₹ 14,500 / प्रतिमास होगी।
- 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
- 4. संविदा पवर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा / होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा / होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनिधकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अविध अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।
- 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ—साथ इ०पी०एफ० / जी०पी०एफ० भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः		
1		
(नाम व पूरा पता)		
2		
(नाम व पूरा पता)		

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में:
1
(नाम व पूरा पता)
2
नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. SJE-A-B(1)-16/2012, dated:26th. June, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh Department of Social Justice and Empowerment

No: SJE-A-B(1)-16/2012 dated: Shimla-02 the 26th. June, 2015

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), Class-II (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement:

- (1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Social Justice and Empowerment, Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), Class-II, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.
- (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

Endst No. As above, dated: Shimla-02 26th. June, 2015 Copy to:-

- 1. The A.C.S./Pr. Secretaries/Secretaries (Finance/Law/Personnel) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-02.
- 2. The Director, SCs, OBCs and Minorities Affairs, SDA Complex, Kasumpti, Shimla-09. He is requested to procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
- 3. The Controller, Printing & Stationary Department, H.P. Shimla-05 for publication into the Govt. Gazette.
- 4. Guard File.

Under Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SPECIAL POST GRADUATE TEACHER (PGT) IT (HEARING IMPAIRED) (CLASS-II-NON-GAZETTED), IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1	Name of the post	Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired)
2	Number of post(s)	01 (One)
3	Classification	Class-II (Non-Gazetted)
4	Scale of Pay	 i) Pay scale for regular incumbent: Pay Band ₹10300-34800 + ₹4200/- Grade Pay ii) Emoluments for contract employee: ₹14,500/- as per details given in Column 15-A.
5	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	Not applicable
6	Age for direct recruitment	45 years and below

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he / she was appointed as such he / she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations / Autonomous Bodies who are / were subsequently appointed by such Corporations / Autonomous Bodies and who are / were finally absorbed in the service of such Corporations / Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector

	Corporations / Autonomous Bodies.				
	<u>Notes</u> :				
	the year in which	1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is / are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.			
	discretion of the Hi	(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.			
7	Minimum educational	(a) Essential Qualification(s):			
	and other qualifications required for direct recruit(s)	Bachelor's degree in Computer Science & Engineering / Computer Application / Information Technology or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.			
		OR			
		i) Master Degree in Physics / Mathematics / Economics / Statistics or its equivalent from a recognized University.			
		ii) Post Graduate Diploma of atleast one year duration in Computer Application or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.			
		OR			
		Master Degree in Information Technology / Computer Science / Computer Application (MCA) or its equivalent from a recognized University or from an Institute duly recognized by the H.P. / Central Government.			
		OR			
		"B" level Course from DOEACC Society.			
8	Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s)	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable			
9	Period of probation, if any	Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special			

		circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.
11	In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion / deputation / transfer is to be made:	Not applicable
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Not applicable
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment	As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the Commission / other recruiting authority, as the case may be.
15- A	Selection for appointment to the post by contract appointment	Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below: - (I) <u>CONCEPT</u> : (a) Under this policy the Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired), in the Department of Social

Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his / her period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. <u>Himachal Pradesh</u> Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Special Post Graduate Teacher (PGT) IT (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @₹14,500/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of ₹435/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) <u>APPOINTING</u> / <u>DISCIPLINARY</u> AUTHORITY:

The Principal Secretary / Secretary (SJ&E) to the Government of H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. <u>Himachal Pradesh Public</u> Service Commission.

(V) <u>COMMITTEE FOR SELECTION OF</u> <u>CONTRACTUAL APPOINTMENTS</u>:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the <u>Himachal Pradesh Public Service Commission</u> from time to time.

(VI) <u>AGREEMENT</u>:

After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @₹14,500/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ₹435/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior / selection scales etc. will be given.
- (b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance / conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one-month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He / She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave & Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in

18	Power to relax	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
----	----------------	---
